पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य प्रक्षेत्र)

वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत योजनाओं से संबंधित आलेख :–

(क) राज्य योजना :–

(i) समग्र गव्य विकास योजना :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन तथा प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम पौष्टिक आहार के रूप में दूध एवं दूध जन्य उत्पाद की उपलब्धता को पूरा करना है ताकि राज्य दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹66.49116 करोड़ (रूपये छियासठ करोड़ उनचास लाख ग्यारह हजार छः सौ) मात्र की लागत पर समग्र गव्य विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/बेरोजगार युवक–युवतियों को 50% अनुदान पर दुधारू मवेशी की (2, 5, 10 एवं 20) डेयरी इकाई स्थापित किये जा रहे हैं।

(ii) प्रशिक्षण एवं प्रसार की योजना (सामान्य) :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के कृषकों/दुग्ध उत्पादकों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें गव्य व्यवसाय के बारे में अद्यतन जानकारी दिया जाना है। साथ ही प्रचार–प्रसार के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें पुरस्कृत करते हुए प्रोत्साहित किया जाना है तथा गव्य प्रक्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों को जिला स्तर/राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सेमिनार में स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी एवं लघु फिल्म के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹241.84552 लाख (रूपये दो करोड़ एकतालीस लाख चौरासी हजार पाँच सौ बावन) मात्र के अनुमानित लागत पर 2850 दुग्ध उत्पादकों/ समिति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण राज्य के बाहर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा) एवं राज्य के अन्दर दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान, पटना तथा कम्फेड, पटना में प्रदान करने तथा 1202 दुग्ध समितियों में दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है।

(iii) विशेष अंगीभूत योजना के तहत अनु0 जाति/जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण :–

राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कृषकों/दुग्ध उत्पादकों जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हैं अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हैं, गव्य विज्ञान में विशेष प्रशिक्षण देकर गव्य व्यवसाय हेतु प्रेरित करना है ताकि राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके। चालू वित्तीय वर्ष में कुल ₹107.121 लाख (रूपये एक करोड़ सात लाख बारह हजार एक सौ) मात्र के लागत व्यय पर विशेष अंगीभूत योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के 2070 सदस्यों को राज्य के अन्दर स्थित प्रशिक्षण संसाधन यथा दीप नारायण सिंह सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना एवं कम्फेड, पटना में गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है।

(iv) कम्फेड को एन0 सी0 डी0 सी0 द्वारा प्राप्त ऋण पर देय सूद की राशि का भुगतान :–

कम्फेड द्वारा आगामी पाँच वर्षों में दुग्ध संग्रहण को देखते हुए नये डेयरी संयंत्रों/पशु आहार संयंत्र स्थापित कर उसकी प्रोसेसिंग, विधायन एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु एन0 सी0 डी0 सी0 से ऋण प्राप्त की गई है। जिसपर राज्य सरकार द्वारा सूद का भुगतान की जानी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में एन0 सी0 डी0 सी0 द्वारा कम्फेड को ऋण के रूप में कुल 15 परियोजनाओं के लिए ₹99,54,80,300/- (निनानवे करोड़ चौवन लाख अस्सी हजार तीन सौ) मात्र प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त हुआ है जिसपर वर्ष 2014–15 के लिए देय सूद की राशि ₹12,82,99,465/- (बारह करोड़ बेरासी लाख निनानवे हजार चार सौ पैसठ) मात्र का भुगतान एन0 सी0 डी0 सी0 को कम्फेड के माध्यम से किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

(i) बल्क मिल्क कूलर की स्थापना :–

दुग्ध उत्पादकों द्वारा उत्पादित किये जा रहे दूध की गुणवत्ता को उत्पादन के स्तर पर अक्षुण्ण रखने तथा दूध को तुरन्त ठंडा कर जीवाणुओं की संख्या में होने वाले वृद्धि को रोकर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करने हेतु ₹976.00 लाख (रूपये नौ करोड़ छिहत्तर लाख) मात्र के लागत व्यय पर कुल 77 इकाई बल्क मिल्क कूलर (5000 ली0 क्षमता का 55 इकाई, 3000 ली0 क्षमता का 22 इकाई) स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का क्रियान्वयन कम्फेड, पटना द्वारा किया जा रहा है।

(ii) तरल नाईट्रोजन ट्रॉन्सपोर्ट टैंकर क्रय की योजना :–

दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को सुचारू एवं निर्बाध रूप से संचालित करने हेतु तरल नाईट्रोजन ट्रॉन्सपोर्ट टैंकर के माध्यम से तरल नाईट्रोजन की आपूर्त्ति दुग्ध संघों को किया जाना है। इसके लिए कुल ₹90.00 लाख (रूपये नब्बे लाख) मात्र के लागत व्यय पर 2 इकाई तरल नाईट्रोजन ट्रॉन्सपोर्ट टैंकर क्रय की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। तरल नाईट्रोजन उत्पादन केन्द्र से परिवहन टैंकरों द्वारा तरल नाईट्रोजन परिवहन कर केन्द्रीयकृत भंडार में आपूर्त्ति किया जाना है ताकि तरल नाईट्रोजन का प्रवाह कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर बना रहे। योजना का क्रियान्वयन कम्फेड, पटना द्वारा किया जा रहा है।

(iii) स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना :–

ग्रामीण स्तर पर संग्रहित दुग्ध की गुणवत्ता की जाँच एवं प्राप्त दूध का शीतलीकरण संकलन केन्द्र पर ए0 एम0 सी0 यू0 द्वारा किये जाने की उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹1875.00 लाख (रूपये अठारह करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के लागत व्यय पर 1500 इकाई स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर संग्रहित दूध की गुणवत्ता की जाँच एवं प्राप्त दूध का शीतलीकरण संग्रहण केन्द्र पर ही हो सकेगा। साथ ही आपूर्त्ति कर्त्ता द्वारा आपूर्त्ति किये गये दूध के मूल्य भुगतान में पारदर्शिता होगी। योजना का क्रियान्वयन कम्फेड, पटना द्वारा किया जा रहा है।

(iv) नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेन्ट की योजना :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरियों में संग्रहित किये जा रहे दूध के Fat & SNF की त्वरित जाँच करने, उसकी गुणवत्ता को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं दूध में उपलब्ध प्रोटीन के आधार पर दुग्ध उत्पादकों को मूल्य भुगतान में पारदर्शिता बरतने तथा उपभोक्ताओं को अच्छे Quality का दूध एवं दूध जन्य उत्पाद उपलब्ध कराना है ताकि उपभोक्ताओं को संतुलित आहार के रूप में पशु जन्य उत्पाद के रूप में प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2014–15 में नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेन्ट के अन्तर्गत कुल ₹1040.00 लाख (रूपये दस करोड़ चालीस लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जा रही है जिसके अन्तर्गत क्रमशः (i) ₹243.00 लाख के लागत व्यय पर 5 इकाई मिल्को स्कैन की स्थापना : (ii) ₹162.00 लाख के लागत व्यय पर 6 इकाई ग्लायकोल चिलर की स्थापना : (iii) ₹99.00 लाख के लागत व्यय पर 3 इकाई होमोजिनाईजर की स्थापना : (iv) ₹405.00 लाख के लागत व्यय पर 3 इकाई Pet Bottle लस्सी पैकिंग मशीन की स्थापना (v) ₹131.00 लाख के लागत व्यय पर 91 इकाई पाउच एवं बॉक्स स्टैम्पींग मशीन की स्थापना किये जायेंगे। योजना का क्रियान्वयन कम्फेड, पटना के माध्यम से किया जायेगा।

(v) त्वरित चारा विकास की योजना :–

वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹2450.00 लाख (रूपये चौबीस करोड़ पचास लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य के 33772 हे0 में त्वरित चारा विकास की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत किसानों के बीच Improved/hybrids seed का Kits जिसमें बीज, खाद, रसायन आदि उपलब्ध करा कर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कराना है। इसके तहत किसानों को चारा उत्पादन एवं कटाई तथा रख–रखाव हेतु अत्याधुनिक उपकरण यथा साइलेज यूनिट का निर्माण, घास काटने वाला पावर चैफकटर मशीन, मानव चालित चैफकटर एवं घास काटने वालन मानव चालित मशीन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि चारा उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर हो सके। योजना का क्रियान्वयन कम्फेड, पटना के माध्यम से किया जायेगा।